

सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात कर बिहार के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर की चर्चा

कोसी नदी पर हाईडैम का डीपीआर जल्द बनेगा सीएम की आग्रह को केन्द्र ने माना

मुख्यमंत्री के आग्रह पर : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैम के डीपीआर को शीघ्र पूरा करने का दिया निर्देश



प्रात : किरण

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के साथ नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात कर बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा की। बैठक में केन्द्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं के अनुरूप राज्य

बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की सकारात्मक सहयोग

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक अत्यंत सकारात्मक रही और बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। सोन-फल्गु रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर एवं विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का कार्य भी शीघ्र शुरू कराने के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार और राज्य के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर तेजी से कार्य कर रही है।

आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के आगे बढ़ने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि एवं जल प्रबंधन को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सप्त कोसी परियोजना के संबंध में भी चर्चा हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर कोसी नदी पर हाई लेवल डैम के डीपीआर को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर सहमति बनी कि संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार का एक सदस्य शामिल रहेगा, जिससे परियोजना से जुड़े तकनीकी विषयों में राज्य के हितों को प्रभावी रूप से रखा जा सके। बिहार को एसएनए& स्पर्स के माध्यम से अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे

राहुल गांधी कानून का सम्मान करें, अराजकता न फैलाएं: रविशंकर

प्रात : किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। बिजपा के मुताबिक जिस मामले को लेकर राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। राहुल गांधी बिना पूर्व अनुमति संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे, जबकि पुलिस पहले स्पष्ट कर चुकी है कि मामले में एफआईआर दर्ज है और जांच जारी है। भाजपा सांसद

सभी जिलों में ‘स्केल-अप एंड मार्केट एक्सेस’ कार्यक्रम आयोजित

- विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर 6,000+ इनोवेटर्स ने लिया भाग
- उद्यमियों को सरकारी सहयोग, विभागीय सुविधाओं, प्रक्रियाओं, नियामकीय अनुपालन एवं व्यवसाय विस्तार से जुड़े अवसरों की जानकारी

प्रात : किरण

पटना। विश्व उद्यमिता दिवस 2026 के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से स्टार्टअप

- मुख्यमंत्री ने कहा- बिहार बदलाव के करीब खड़ा है
- अगले पांच वर्षों में खनन क्षेत्र से लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपए राजस्व अर्जित करने की कार्ययोजना

प्रात : किरण

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने द इकोनॉमिक टाइम्स के कार्यक्रम वर्ल्ड लीडर्स फोरम में बिहार के विकास की भावी दिशा, निवेश की संभावनाओं, आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन, रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार बदलाव के करीब खड़ा है।

बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लंबे समय तक किसी कारणवश बिहार विकास की दौड़ में पीछे रह गया था लेकिन अब मूलभूत आवश्यकताओं-सड़क, बिजली और पानी के क्षेत्र में लगभग सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अब सरकार का विशेष फोकस उद्योग, निवेश और रोजगार पर है, इसके लिए अनेक नई नीतियां बनाई गई हैं ताकि देश-दुनिया के निवेशकों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सुशासन को प्राथमिकता देते हुए सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब तक 6 लाख 42 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। विशेष नीतियां बनाई गई हैं। उद्योगों को जमीन, बिजली और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

कोसी नदी को अभिशाप से वरदान में बदलना सरकारी का लक्ष्य: कोसी नदी को अभिशाप से



वरदान में बदलना सरकार का लक्ष्य है। कोसी और गंडक उत्तर बिहार की दो प्रमुख नदियां हैं। गंगा, गंडक और कोसी के दोनों किनारों पर एकीकृत फोर लेन सड़क तथा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की परिकल्पना की जा रही है। गंगा और गंडक के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एजुकेशनल हब, इंस्टीट्यूशनल हब और बड़े टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। बिहार को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे ले जाकर उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन और जलमार्ग से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।

अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 के चुनाव से पहले तक 53 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की गई है। बिहार में 40 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सर्वाधिक है। **बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध :** मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता की आकांक्षाएं सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। अगले चार वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था को चार गुना करने का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं

संक्षिप्त खबरें

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा: राष्ट्रपति भवन में पूर्ण अभ्यास की तैयारी

नईदिल्ली। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की आगामी भारत यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। उनके औपचारिक स्वागत की तैयारियों के तहत राष्ट्रपति भवन ने साप्ताहिक ह्यूजेज ऑफ गार्डोल्ड समारोह को रद्द करने की घोषणा की है ताकि स्वागत समारोह का पूरा अभ्यास किया जा सके। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले ह्यूजेज ऑफ गार्डोल्ड समारोह (सुरक्षा गार्डों को बदले जाने से जुड़ा एक सैन्य कार्यक्रम) इस शनिवार (22 अगस्त, 2026) को नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत के लिए पूर्ण अभ्यास किया जाना है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के लिए रहमान की प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा को लेकर राजनयिक अनिश्चितता बनी हुई है। यह अनिश्चितता दोनों पड़ोसी देशों के बीच हालिया तनाव के कारण है, जो ढाका की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग किए जाने से पैदा हुई है।

350 से अधिक सुपारी किलर की सूची तैयार, दबोचने की कार्रवाई शुरू

- एसटीएफ की प्रेस वार्ता में डीआईजी ने दी जानकारी, अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी

प्रात : किरण

पटना। राज्य में एसटीएफ (विशेष टॉस्क फोर्स) अपराधियों को किसी घटना को अंजाम देने के बाद गिरफ्तार कर ही रही है। बल्कि, विशेष खुफिया तंत्र और सशक्त पुलिसिंग की बदौलत किसी अपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले भी अपराधियों को दबोच रही है। पुलिस महकमा की विशेष इकाई एसटीएफ ने राज्यभर में 350 से अधिक सुपारी किलर की सूची तैयारी की है और इन्हें दबोचने की कवायद भी तेजी से कर रही है।

इस कवायद से सुपारी किलिंग नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। यह जानकारी एसटीएफ के डीआईजी श्री संजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी से अब तक 1716 अपराधियों को गिरफ्तार

किया जा चुका है। ये सभी अपराधी चाहे टॉप-10 या हार्डकोर अपराधियों की श्रेणी में शामिल हैं। इनमें 63 अपराधियों पर जिला या राज्य स्तर पर ईनाम भी घोषित हैं। विभिन्न तरह की अपराधिक वारदातों में शामिल 27 अपराधियों को राज्य के बाहर से भी गिरफ्तार करके लाया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधिक वारदात के 94 मामलों को घटना होने से पहले ही रोक लिया गया, जिसमें हत्या के 40, डकैती एवं छिन्नैती के 48 और अन्य तरह के अपराध से जुड़े 6 मामले शामिल हैं। डीआईजी ने कहा कि पिछले 8 महीनों के दौरान अपराधियों के साथ पुलिस के 19 मुठभेड़ हुए, जिसमें 3 अपराधी मारे गए और 18 घायल हो गए हैं। इन मुठभेड़ों के माध्यम से कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करते हुए क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत की गई है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध को रोकने के लिए जिलावार विशेष कार्य बल के तेनात पदाधिकारी के स्तर से सक्रिय गिरोहों और इसके सदस्यों के संबंध में तैयार डाटाबेस के आधार पर संगठित गिरोहों के खिलाफ अभियान में गुप्तचर गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें भू-माफियाओं को भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और उनके स्तर

से अर्जित अवैध संपत्ति की पहचान कर पीएमएलए (प्रोवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई करने के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि इस वर्ष अब तक 33 मिनो गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इस दौरान 1 एके-47 रायफल, दो एसएस रायफल के अलावा 398 देशी हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1300 राउंड गोली भी बरामद की गई है। इसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एनआईए के स्तर से भी जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बैंक, ज्वेलरी और गोल्ड लूट गिरोहों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष करीब 10 किलो लूटे गए सोना, 50 किलो चांदी और 11.97 लाख कैश बरामद किए गए हैं। इसमें कर्नाटक के मैसूर स्थित ज्वेलरी शॉप लूट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के दादरनगर थाना में हुई लूट, उड़ीसा के कोईझर जिला बरबिला थाना में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा लूट कांड जैसे अन्य कई प्रमुख कांडों का खुलासा किया गया है। इन मामलों में शामिल 113 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि साईबर अपराध से जुड़े 19 मामलों को भी हल किया गया।



विकास के लिए संसाधनों के अपत्यय को नियंत्रित और परिणामदयी बनाना जरूरी: उपमुख्यमंत्री

- बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव-2026 का हुआ समापन
- एसडीजी को जिला योजना एवं योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़कर विकसित बिहार-2047 की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर

पटना। बिहार में सतत एवं समावेशी विकास को गति देने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय बिहार एसडीजी कॉन्क्लेव-2026 का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्तीय क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, लेकिन विकास के लिए संसाधनों के अपव्यय को नियंत्रित करना और प्रत्येक व्यय को परिणामदयी बनाना जरूरी है। पटना में मुख्य सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में विकसित बिहार 2047 की दिशा में तीव्र प्रगति विषय

नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 119 लाभुकों को दिया योजनाओं का लाभ

- 5 लाख रुपये से अधिक का सौपा चेक

पटना। ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री एवं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने शुक्रवार को नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड में 119 लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने पांच लाख रुपये से अधिक राशि के चेक लाभुकों को सौंपे। मंत्री ने शौचालय निर्माण के लिए जीविका दीदियों को आर्थिक सहयोग दिया। कुल 29 जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये की

बिहार की राजकोषीयस्थिति अत्यधिक दयनीय औरचिंतनीय है: तेजस्वी

- नेता प्रतिपक्ष ने कहा - बिहार गंभीर आर्थिक संकट में

पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वित्तीय स्थिति को लेकर एक बात फिर सरकारी को खिंचाई की है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार की राजकोषीय स्थिति अत्यधिक दयनीय और चिंतनीय है। बिहार भारी कर्ज में है। कुल सार्वजनिक ऋण में चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है। बिहार को गंभीर आर्थिक संकट में धकेला जा चुका है। बिहार की वित्तीय स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि सारा खजाना खाली है। वित्तीय दबाव इतना अधिक है कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों, पेंशनधारकों को ससमय सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदारों के बकाये भुगतान और अन्य विकाससाहक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। अब तो छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को राशि भी घटा दी गयी है। छात्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का राजकोषीय स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। राजस्व घाटा बढ़ रहा है और कर्ज उससे भी कई गुना अधिक बढ़ रहा है। विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा बिहार ने दर्ज किया, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.8 प्रतिशत था। बिहार में उच्च घाटे के साथ-साथ

लढ़ाख की सिंधु यात्रा के लिए आवेदन शुरू, बिहार सरकार की आर्थिक सहायता योजना का लें लाभ

18 वर्ष से अधिक आयु के स्थायी निवासी होंगे पात्र, यात्रा पूरी होने के बाद 60 दिनों में करना होगा आवेदन

- यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेगी सहायता, वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी योजना

पटना। बिहारवासियों के लिए लेह-लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा अब आर्थिक रूप से आसान होने जा रही है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने ह्हासिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना-2026ह्ह के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पात्र बिहारवासियों को सिंधु दर्शन यात्रा पूरी



पर आयोजित दो दिवसीय कॉन्क्लेव में आर्थिक परिवर्तन, समावेशी विकास, जिला आधारित योजना, एसडीजी के स्थानीयकरण और विकसित बिहार 2047 की प्राथमिकताओं पर मंथन हुआ। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि वक्त के साथ जरूरत बदलती है, इसलिए समय और तकनीक के साथ स्वयं को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए उचित व्यय, नई तकनीक और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यप्रणाली जरूरी है। उन्होंने बताया कि बिहार मौसम सेवा केंद्रों के क्षेत्र में अग्रणी है और पंचायत स्तर तक

मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, विज्ञान और ईमान से काम करें, फिर हम सम्मान की अपेक्षा करें। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि दुनिया की 55 फीसदी आबादी शहरों में रहती है। शहरों में बसने वाले लोगों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 80 फीसदी से भी अधिक का योगदान रहता है। इसलिए सरकार राज्य के 12 शहरों में टाउनशिप के विकास पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन टाउनशिप में बसने वाले आबादी के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इंटरनेट, गुणवत्तायुक्त

सड़क, पार्क, एजुकेशन, स्पोर्ट्स आदि सुविधाओं के साथ पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक पहलुओं को लागू किया जाएगा। **स्वच्छता एवं नलजल में बिहार ने पेश की नजीर : डॉ. एन. विजयलक्ष्मी-** कार्यक्रम में योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने कहा कि बिहार को छोड़कर भारत आगे नहीं बढ़ सकता, भारत का विकास बिहार के विकास से ही संभव है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ जल और स्वच्छता श्रेणी में 98 अंकों के साथ बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। इस योजना के तहत सितंबर 2025 तक 26,960.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 1.75 करोड़ ग्रामीणों को नल का कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच राज्य में बहुआयामी गरीबी (एमपीआई) 51.8 फीसदी से घटकर 33.7 फीसदी हो गई है। इस दौरान लगभग 2.25 करोड़ लोग पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में बिहार की आबादी के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इंटरनेट, गुणवत्तायुक्त

मेगा जॉब फेयर : तीसरे दिन 3487 युवाओं का चयन

पटना। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मेगा जॉब फेयर-2026 युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर का मंच बनकर उभरा है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित इस मेगा जॉब फेयर के तीसरे दिन करीब 9 हजार युवाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा 3487 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार की तलाश में बिहार के अलग-अलग जिलों से पहुंचे युवाओं में मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

100 से अधिक कंपनियां दे रहीं रोजगार के अवसर: मेगा जॉब फेयर में एचबीआई लाइफ, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस रिटेल,

9.8 फीसदी से भी काफी अधिक है। **प्रस्तुत सुझावों को नीतियों में शामिल करने का आश्वासन: केवी राजू** –कार्यक्रम में मौजूद नीति आयोग के सदस्य केवी राजू ने कहा कि संगोष्ठी में प्रस्तुत सुझावों को वह आयोग में शामिल करेगा। बशर्ते प्रस्ताव योजना विभाग की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने डेटा कलेक्शन और पंचायत स्तर पर इंडेक्स बनाकर जल्दतमद लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर पूर्व विकास आयुक्त डॉ. एस. सिद्धार्थ, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार, जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह, पटना डीएम कुंदन कुमार, मधुबनी डीएम श्री आनंद शर्मा आदि ने पीपीटी के माध्यम से भविष्य की योजनाओं से रूबरू कराया। इस अवसर पर वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल, नृसिंसेफ की प्रतिनिधि क्रिस्टिना पोपिवानोवा समेत केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

टाटा क्रोमा, टाटा मोटर्स, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, विजन इंडिया, जॉनसन लिफ्ट, मैनुपावर ग्रुप, मास एचआर सॉल्युशन, एनआईआईटी फाउंडेशन, रीशव ऑटोमोबाइल, सत्या माइक्रोकैपिटल लिमिटेड और अन्यपूर्णा फाइनेंस समेत 100 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एवं इंश्योरेंस (बीएफएसआई), रिटेल, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता, कौशल और रुचि के अनुरूप रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

एक ही छत के नीचे पंजीकरण से चयन तक की प्रक्रिया: जॉब फेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को रोजगार के लिए अलग-अलग कंपनियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ज्ञान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है बिहार : नीतीश

- सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार एवं कन्वेजीनियस.एआई के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

पटना। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी क्षमताओं के विकास एवं रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार एवं कन्वेजीनियस.एआई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा की गरिमाययी उपस्थिति में किए गए। बिहार को एक एआई-सक्षम राज्य के रूप में विकसित करने तथा राज्य में एआई आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह एमओयू हुआ है। इस अवसर पर मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि

एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम राज्य बनाना है। एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निवेश, उच्च कौशल वाली तकनीकी क्षमताओं का विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन इसी विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने बताया कि कन्वेजीनियस.एआई भारत की अग्रणी एआई-नैटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, जो बड़े पैमाने पर एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और एआई सॉल्यूशंस के डिप्लॉयमेंट के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी टेक्नोलॉजी, एकेडमिक डिजाइन, इमैक्टेड असेसमेंट एवं चेंज मैनेजमेंट के क्षेत्रों में 500 से अधिक प्रोफेशनल्स की टीम के साथ कार्य कर रही है। कंपनी की कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पार्टनरशिप और ऑनगोइंग एगेंजमेंट हैं। इसके साथ ही कन्वेजीनियस डेटा एआई की तरफ से गवर्नमेंट एवं एंटरप्राइज यूजर्स के लिए विभिन्न एआई एप्लिकेशंस और इंटेलिजेंट एजेंड्स विकसित किए जाते हैं, जिनका उपयोग व्हॉट्सऐप, आईबीआर, वेब और एंड्रॉयड जैसे माध्यमों के जरिए नागरिक सेवाओं, शिक्षा, कल्याण एवं कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है।

युवाओं के लिए नए अवसरों को मिलेगा प्रोत्साहन: मंत्री नीतीश

शिक्षा ऋण योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा: कुंतल

पटना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि बिहार सरकार की शिक्षा ऋण योजना को लेकर विपक्ष और जन सुराज भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना पहले की तरह जारी है, बल्कि इसका दायरा और लाभ बढ़ाया गया है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि अब सामान्य रूप से 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है, जबकि 164 महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें 2 लाख रुपये तक का ऋण बिहार शिक्षा वित्त निगम और 2 से 4 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के सहयोग से उपलब्ध कराया जाएगा। 10 लाख रुपये तक का ऋण बिहार सरकार की योजना के तहत विहित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की योजना केंद्र की योजना से अधिक व्यापक है। केंद्र की योजना में 4.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को शतप्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है, जबकि इससे अधिक आय वालों को केवल 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है और लाभ अधिक पाठ्यक्रमों तक सीमित है। बिहार में सभी आय वर्ग के परिवारों और अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को भी शतप्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पाठ्यक्रम की अवधि और एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि तक पूरा ऋण ब्याजमुक्त रहेगा। इसके बाद समय पर ऋण चुकाने वाले विद्यार्थियों को 30 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट तथा छात्राओं को कुल 40 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पैसा सभी बच्चों का है। ऋण की वसूली नहीं होने पर नए विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रभावित होगा। अब तक 4,15,938 लाभार्थियों को 8,865 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। इनमें 1,63,274 लाभार्थियों से 1,263 करोड़ रुपये की वसूली योग्य है, जबकि 46,979 लाभार्थियों से 273.18 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है। लगभग 79 प्रतिशत की डिफॉल्ट दर चिंता का विषय है।

चीनी की बढ़ती कीमत के लिए सरकार जिम्मेदार : एजाज

पटना। देशभर में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राजद नेता एजाज अहमद ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार से पहले चीनी की बढ़ती कीमत कहीं ना कहीं लोगों के मिठास को कम कर देगा और इससे त्योहार की खुशियों में खलल पड़ेगा। एजाज अहमद ने आगे कहा कि गन्ने का बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन में उपयोग किए जाने के कारण चीनी का उत्पादन और उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसी वजह से बाजार में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति तो बनाई, लेकिन इससे आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को नजरअंजक कर दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि त्योहारों को देखते हुए चीनी के दाम कम करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएं। और कालाबाजारी और जमाखोरों पर कार्रवाई करें।

लोजपा आर अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठमें पंकज पासवान को प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी



पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सांठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ में पंकज पासवान को प्रदेश अध्क्ष परशुराम पासवान ने आज श्री पंकज पासवान को नियुक्ति पत्र दिया। उनके मनोमयन से पार्टी कार्यक्रमों में उत्साह का माहौल है। पार्टी ने पंकज पासवान की सक्रियता, संगठन के प्रति समर्पण तथा सामाजिक सरोकारों को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में वे अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ की गतिविधियों, पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को मीडिया और आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंकज पासवान के मनोमयन पर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। शुभकामनाएं देने वाले नेताओं में युवा लोजपा-(रा) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु पासवान, आनन्द कुमार, सुजीत कुमार, रंजीत कुमार, राबिंस कुमार, सिद्धार्थ कुमार, दिग्विजय कुमार, सूरज राज गुप्ता शामिल थे।

आम उपभोक्ता महंगाई से त्रस्त : भाकपा

पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीयपी कार्यक्रम के तहत बदलाव जरूरी है 01 सितम्बर, 2026 दिल्ली चलो नारों के साथ 06 अगस्त से शुरू की गयी पदयात्रा का कार्यक्रम राज्य में जारी है। गांव-गांव पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। पदयात्रा को काफी संख्या में लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है। बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यक्रमों, हमदर्द, समर्थक और आम लोगों की भागीदारी हो रही है और गोष्ठी एवं सभा का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि पदयात्रा एवं 01 सितम्बर, 2026 दिल्ली रैली की जो रिपोर्ट मिल रही है वह काफी उत्साहजनक है। काफी संख्या में लोग 01 सितम्बर, 2026 को दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित बदलाव जरूरी है रैली में भाग लेने हेतु जाने के लिये तैयारी कर रहे है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान आम लोगों ने संवाद के दौरान बताया कि केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति के चलते आम उपभोक्ता महंगाई से परेशान है।



मुजफ्फरपुर

मनिकपुर-साहेबगंजफोरलेन निर्माण को गति देने में जुटा प्रशासन, डीएम ने किया एलाइनमेंट का निरीक्षण

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। एनएच-139डब्ल्यू के तहत मनिकपुर-साहेबगंज फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने परियोजना के संपूर्ण एलाइनमेंट का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जमीनी प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण

का मुख्य उद्देश्य भू-अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़ी बाधाओं को दूर कर सड़क निर्माण में तेजी लाना था।निरीक्षण के दौरान डीएम ने एनएचएआई छपरा के परियोजना निदेशक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, निर्माण एंजेंसी के प्रतिनिधियों और संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से

भू-अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।परियोजना के लिए जिले के 36 मौजों में कुल 183.96 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए कुल 413.02 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि निर्धारित की गई है। भू-अर्जन विभाग की ओर से अब तक रैयतों के बीच 332.03 करोड़ रुपये के मुआवजे का वितरण किया जा चुका

है। समीक्षा के दौरान भूमि विवाद और न्यायालय में लंबित मामलों के कारण मुआवजा भुगतान में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में सुनवाई और आपसी वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन रही है, उन विवादित मामलों के एनएच अधिनियम 1956 की धारा 3एच(4) के तहत तत्काल व्यवहार न्यायालय भेजा जाए। जिलाधिकारी

ने कहा कि कानूनी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करते हुए संबंधित राशि न्यायालय में जमा कराई जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अड़चनें दूर हों और फोरलेन निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एंजेंसी को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।

उत्तर बिहार के कई जिलों में25-26 अगस्त को भारी बारिश की संभावना

मुजफ्फरपुर। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 22 से 26 अगस्त तक उत्तर बिहार में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 25-26 अगस्त के आसपास बेगुसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कुछ स्थानों पर गरिज-चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुल 45 से 65 मिलीमीटर तक वर्षा का अनुमान है।पुर्वानुमान अर्थां में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम को देखते हुए मक्का की फसल में तना छेदक और फॉल आर्मीवर्म की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। तना छेदक के नियंत्रण के लिए काबोफ्थुरान 3 जी तथा फॉल आर्मीवर्म के लिए इमांमेक्टिन बेंजोएट के प्रयोग की सलाह दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर सात दिन बाद कोराजेन का छिड़काव किया जा सकता है।धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के साथ तना छेदक एवं पत्ती लोपटक कीटों पर नजर रखने को कहा गया है। प्रकोप होने पर क्लोरेंट्रानिलप्रोल 4 जी दानेदार दवा के प्रयोग की सलाह दी गई है। किसानों को परवल की बुवाई करने की सलाह देते हुए उत्तर बिहार के लिए राजेंद्र परवल-1, राजेंद्र परवल-2, राजेंद्र परवल-3, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण सुरभि किस्मों को उपयुक्त बताया गया है। बैंगन में तना एवं फल छेदक कीट के शुरुआती प्रबंधन के लिए रोपाई के 10 दिन बाद फ्यूराडान 3-जी के प्रयोग की सलाह दी गई है। संक्रमित टहनियों और फलों को तोड़कर मिट्टी में दबाने तथा अधिक प्रकोप की स्थिति में स्पिनोसेड के छिड़काव को उपयोगी बताया गया है।

मसालों पर क्रेता - विक्रेता सम्मेलन आयोजित

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। बिहार के मसालों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की बड़ी पहल के तहत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के स्पाइसेस बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को विद्यापति सभागार, आरपीसीएयू, पूसा में *मसालों पर क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया।इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार से मसाला निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों, एफपीओ , किसान समूहों, मसाला उद्योग के हितधारकों और देश भर के निर्यातकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉ. पी. एस. पाण्डेय और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बंशिश नारायण झा, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड उपस्थित रहे। सम्मेलन का आयोजन संदीप कुमार चौरसिया,



क्षेत्रीय कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, कोलकाता एवं डॉ. ए. के. मिश्रा, प्रधान अन्वेषक, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (मसाला), आरपीसीएयू द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बोलेतु हुए कृषिपरि डॉ. पी. एस. पाण्डेय ने कहा कि मसाला क्षेत्र में बिहार का समय आ गया है। उन्होंने कहा, कि बिहार अब सिर्फ अनाज का कटोरा नहीं है; यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया और विशेष रूप से एशिया का मसाला हब बन सकता है। बिहार की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ हल्दी, अदरक,

धनिया, मेथी और अन्य उच्च मूल्य वाले मसालों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि यहां की चुनौती उत्पादन की नहीं, बल्कि लॉजि, गुणवत्ता, मार्केटिंग, निर्यात और मूल्य संवर्धन की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मसालों के विभिन्न उन्नत किस्मों, कटाई उपरांत तकनीकों और बाजार लॉजिस्टिक्स विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा इस क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से विश्वविद्यालय किसानों को कृषि-उद्यमी बनाने का प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय और स्पाइसेज

कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर में गूजे वैदिक मंत्र, सावन भर रुद्राभिषेक और महाप्रसाद का आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के कुशी हरपुर रमणी स्थित ऐतिहासिक कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर में शुक्रवार को आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर में विधि-विधान के साथ रुद्राभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन और महाआरती का आयोजन किया गया। पूजन और बाबा कुशेश्वरनाथ के दिव्य श्रृंगार के बाद मंदिर प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा तय की गई। मंदिर कमेट्री के अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि पवित्र सावन मास में भगवान शिव की विशेष आराधना की जा रही है। पूरे सावन मास में प्रतिदिन सुबह विशेष रुद्राभिषेक, वैदिक हवन और पूजन करणया जा रहा है। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। वहीं, प्रत्येक दिन संख्या वेला में विशेष पूजन और भव्य महाआरती का आयोजन कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर सुबह विशेष रुद्राभिषेक के बाद बाबा कुशेश्वरनाथ का दिव्य महाश्रृंगार किया जाएगा। आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए एडि्टर समिति के सदस्य पूरी तरह जुटे हुए हैं। शुक्रवार को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान और बैठक में मंदिर कमेट्री के सदस्य गौतव त्रिवेदी, उर्कष त्रिवेदी, हेमंत त्रिवेदी, मुन्ना तिवारी, रमेश मिश्रा, मणि मोहन कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। मंदिर परिसर पूरे दिन हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजाता रहा।

स्कूल में चोरी और तोड़फोड़ के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, बनास बैंक चौक जाम

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। शहर के महिला शिल्पकला विद्यालय में चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को छात्रों का आक्रोश उबल पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और बनास बैंक चौक को जाम कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के सड़क पर उतरने से यातायात प्रभावित हो गया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। छात्रों के मुताबिक, दो दिन पहले विद्यालय से चार पंखे चोरी हुए थे। इस मामले में गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में छात्रों व संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। छात्रों का कहना

है कि इसके बावजूद गुरुवार की रात विद्यालय परिसर से सनसिंबल मोटर भी चोरी हो गई। लगातार चोरी की घटनाओं से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चोरी की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई और विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। छात्रों के प्रदर्शन और सड़क जाम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा मामलों की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रों व संबंधित लोगों की कोशिश की जा रही है।

रूपौली विशाणपुर में महिला का शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस

मुजफ्फरपुर। रामपुर हरि थाना क्षेत्र के रूपौली विशाणपुर गांव में एक महिला का शव फंदे से लटका मिलने का बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अन्नजोत पासवान की 36 वर्षीय पत्नी अमिता देवी के रूप में हुई है। वह तीन बच्चों की मां

थी। बताया गया कि महिला का शव फंदे से लटका मिलने की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रामपुर हरि थाना पुलिस को

अपराधियों ने हथियार के बल पर मुंशी से लूटे 3.18 लाख

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। आलू-प्याज कारोबारी के मुंशी से हथियार के बल पर अपराधियों ने 3.18 लाख रुपए लूट लिए। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ओवरब्रिज के पास गुरुवार देर रात की बताई गई है। मुंशी श्रीकांत के अनुसार , वह बाजार समिति स्थित दुकान बंद कर रात में घर लौट

रहा था। चांदनी चौक ओवरब्रिज के नीचे पहले से घात लगाए बैठे छह नकाबपोश अपराधियों उसे रोक लिया। कनपटी पर पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दी और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बैग में दुकान की दिनभर की बिक्री के कुल 3 लाख 18 हजार रुपए नकद थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी अपनी बाइक पर सवार होकर हथियार लहराते

हुए मुख्य सड़क की ओर फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस और दुकान मालिक को मामले की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित मुंशी का पूरा बयान दर्ज किया। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके।

बाबा गरीबनाथ धाम के कायाकल्प की तैयारी तेज, फकुली में बनेगा भव्य स्वागत द्वार

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार के देवघर के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ धाम के कायाकल्प और भव्य कॉरिडोर निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने जिलाधिकारी और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जिले के प्रवेश द्वार फकुली स्थित प्रस्तावित तोरण द्वार स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि संदेश का उद्देश्य बाबा गरीबनाथ धाम को राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इसके तहत



फकुली में भव्य स्वागत द्वार का निर्माण कराया जाएगा, जो मुजफ्फरपुर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। इसके अलावा शहर के छाता बाजार और साहू चौक पर भी विशेष थीम आधारित भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत ऐतिहासिक साहू पोखर का भी कायाकल्प किया जाएगा। यहां आकर्षक आरती डेक के साथ ललास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांवरिया पथ

बिस्किट में जहर देकर ढाई साल के बच्चे की हत्या का आरोप, मां हिरासत में

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। रामपुर हरि थाना क्षेत्र के टेंगराहां उत्तर टोला में गुरुवार दोपहर करीब ढाई साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे के दादा ने उसकी मां पर बिस्किट में कथित तौर पर जहर मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद रामपुर हरि थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मौत हत्या की वजह से हुई या किसी अन्य कारण से, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मुजफ्फरपुर में करीब दो साल पहले भी एक मां पर अपनी बेटी की हत्या का मामला सामने आया था। 24 अगस्त 2024 को मिटनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाबा शास्त्री नगर में एक टॉली बैग से करीब साढ़े तीन साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था। बच्ची की पहचान गया के चाकन्द बाजार निवासी मनोज लाल की बेटी मिथी कुमारी के रूप में हुई थी। पुलिस की जांच में बच्ची की मां काजल कुमारी को आरोपी बनाया गया था। घटना के अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ में काजल ने कथित तौर पर प्रेमी से शादी करने के लिए बच्ची की हत्या करने की बात कही थी। पुलिस के अनुसार, उसने क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या की योजना बनाई थी। फिलहाल टेंगराहां उत्तर टोला में हुई ताजा घटना को लेकर पुलिस आरोपी मां से पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।

विश्व उद्यमिता दिवस पर जिलास्तरीय स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सेल के संयुक्त तत्वावधान में स्केल अप एंड माइक्रो एक्सेस विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में जिलाधिकारी कुमार गौरव शंकर प्रसाद ने भी छात्रों एवं उद्यमियों के संबोधित किया। उन्होंने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए उद्योग विभाग, बिहार सरकार से सीड फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यक चरणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. मनीष कुमार ने छात्रों को अपने-अपने क्षेत्र में नवाचार एवं नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा और नए विचारों के



माध्यम से समाज एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं कार्यक्रम में स्टार्टअप सेल के फैकल्टी ईंचार्ज डॉ. किशोर पाथं तथा एमआईटी स्टार्टअप सेल के फैकल्टी ईंचार्ज डॉ. संजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्टार्टअप के संस्थापकों ने अपनी सफलता की कहानी, संघर्ष, अनुभव और उद्यमिता के सफर को छात्रों के साथ साझा किया। इससे छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की व्यावहारिक जानकारी मिली। कार्यक्रम के अंत में प्रोजेक्ट मैनेजर आशुतोष कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन में मुजफ्फरपुर में जिला स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर श्री कुणाल सिंह एवं श्री राकेश कुमार साह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम ने मुजफ्फरपुर के छात्रों, युवा उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों को सरकारी योजनाओं, फंडिंग, मार्केट एक्सेस तथा स्टार्टअप को स्केल करने के अवसरों की जानकारी देने के साथ-साथ विहार में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल का संदेश दिया।

मजदूरी के पैसे मांगने पर युवक की पिटाई पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टेंगराही पंचायत के वार्ड संख्या-2 में मारपीट में घायल 35 वर्षीय युवक मनोज सहनी को बिहार सुबह पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक स्व. रामदेव सहनी का पुत्र था और राजमिस्त्री के रूप में मजदूरी करता था। जानकारों के अनुसार, मनोज सहनी वाई सदस्य तपेश्वर सहनी के बेटे वीरेंद्र सहनी की ठीकेदारी में राजमिस्त्री का काम करता था। आरोप है कि 17 अगस्त को वह मजदूरी के बकाया

उठाया, इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच के साथ घटना से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।



स्कूलो के दरवाजे पर मीडिया का पहरा, लेकिन बच्चों के हाथों में सोशल मीडिया की खुली दुनिया

बचपन कभी किताबों, खेल के मैदान, परिवार की बातचीत और दोस्तों की संगत में गुजरता था। आज वही बचपन मोबाइल की चमकती स्क्रीन में सिमटता जा रहा है। बच्चे घर में मौजूद हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। परिवार सामने बैठा है, मगर संवाद कम होता जा रहा है। किताबें अलमारी में बंद हैं और मोबाइल की स्क्रीन दिन-रात खुली है। यह बदलाव केवल जीवनशैली का परिवर्तन नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। राजस्थान में विधानसभा में शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए जवाब ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। सरकार से पूछा गया था कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूर रखने और पुस्तकों, अखबारों तथा पत्रिकाओं के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गईं और उन पर कितना बजट खर्च हुआ। जवाब में बताया गया कि इस संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन या विचाराधीन नहीं है। यह स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन बच्चों के हाथों में मौजूद उस डिजिटल दुनिया को लेकर ठोस नीति नजर नहीं आती, जहां वे प्रतिदिन घंटों अपना समय बिता रहे हैं। स्कूल के बाहर मोबाइल पर क्या देखा जा रहा है, किससे बातचीत हो रही है, किस तरह की सामग्री बच्चों तक पहुंच रही है और उसका उनके व्यवहार पर क्या असर पड़ रहा है, इन सवालों का जवाब केवल परिवारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मोबाइल और सोशल मीडिया अपने आप में दुश्मन नहीं हैं। तकनीक शिक्षा, जानकारी और संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। समस्या तब पैदा होती है जब तकनीक साधन से बढ़कर आदत और फिर निर्भरता बन जाती है। लगातार छोटे-छोटे वीडियो देखने, बार-बार सूचनाएं जानने और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया पाने की आदत बच्चे के ध्यान को लगातार भटका सकती है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ही देर में मोबाइल देखने की इच्छा होती है। किताब का एक पन्ना लंबा लगता है, लेकिन वीडियो की लगातार बदलती तस्वीरें आकर्षित करती रहती हैं। इसका असर धीरे-धीरे पढ़ाई की आदत पर पड़ सकता है। धैर्य से किसी विषय को समझने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और तत्काल मनोरंजन की आदत गहरी हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह परिवर्तन अक्सर परिवार को तब दिखाई देता है जब बच्चे के व्यवहार में स्पष्ट बदलाव आने लगता है। यह छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है, बातचीत से बचता है, परिवार के साथ बैठने में रुचि नहीं दिखाता और मोबाइल हटाने पर अरुहज या नाराज हो सकता है। हर बच्चे में इसका असर एक जैसा नहीं होता, लेकिन अत्यधिक और अनियंत्रित स्क्रीन इस्तेमाल को सामान्य मान लेना खी उचित नहीं है। चिड़चिड़ापन केवल व्यवहार नहीं, संकेत भी है। बच्चे का चिड़चिड़ापन कई कारणों से हो सकता है। पढ़ाई का दबाव, परिवारिक वातावरण, नौद की कमी, सामाजिक परिस्थितियाँ और अन्य कारण भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चे की दिनचर्या का केंद्रीय हिस्सा बन जाएं, तब उसके व्यवहार में आए बदलाव पर परिवार और विद्यालय दोनों को ध्यान देना चाहिए। रात दैर तक स्क्रीन देखने से नींद की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। नींद पूरी न होने पर अगले दिन थकान, ध्यान की कमी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। लगातार आभासी दुनिया में रहने से वास्तविक जीवन की बातचीत और गतिविधियों में रुचि कम हो सकती है। बच्चा दोस्तों और परिवार के बीच होते हुए भी मानसिक रूप से स्क्रीन की दुनिया में मौजूद रह सकता है। यही वह स्थिति है जहां माता-पिता को केवल मोबाइल छीन लेने के बजाय बच्चे से बातचीत करनी होगी। डांट और डर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। बच्चे को यह समझाना होगा कि मोबाइल जीवन का हिस्सा हो सकता है, जीवन का केंद्र नहीं। परिवार से दूर होता बचपन आज कई घरों में एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। एक कमरे में पूरा परिवार बैठा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी-अपनी स्क्रीन में व्यस्त है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि माता-पिता स्वयं हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो केवल बच्चों से मोबाइल दूर रखने की अपेक्षा करना कठिन होगा। बचपन को परिवार की बातचीत चाहिए। दादा-दादी की कहानियां चाहिए। माता-पिता का समय चाहिए। दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। माता में हार-जीत का अनुभव चाहिए।

मैदान मिले तो ओलंपिक तक उड़ान भर लें गांव की लड़कियां

राजस्थान के लूणकरणसर से करीब 20 किमी दूर बसे कुजटी गांव की 17 वर्षीय उर्मिला काब्रूजी खेलना चाहती है। उसका सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और देश के लिए पदक जीतने का है। लेकिन उसके सामने सवाल यह नहीं है कि वह कितना बड़ा सपना देखती है, बल्कि यह है कि उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस गाँव में लड़कियों के लिए नियमित खेल मैदान नहीं है। स्कूल में मैदान जरूर है, लेकिन पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के बीच उर्मिला को अभ्यास के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। घर लौटने के बाद घरेलू काम उसकी प्राथमिकता बन जाते हैं। ऐसे में खेल के लिए समय निकालना उसके लिए असमन नहीं है। परिवार और समाज की सोच भी उसके रास्ते को आसान नहीं बनाती। उनके लिए उर्मिला का भविष्य शादी, घर-परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों से जुड़ा है। इसलिए उन्हें लगता है कि उसे खेल के बजाय घरलू काम सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उर्मिला की कहानी केवल एक लड़की के सपने और संघर्ष की कहानी नहीं है। यह उस सवाल को सामने लाती है कि गाँवों में लड़कियों को अपनी पसंद का खेल खेलने और उसमें आगे बढ़ने के लिए समाज अवसर आखिर किसने मिलते हैं? करीब 2500 की आबादी और लगभग 400 घरों वाले कुजटी गाँव में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहां की साक्षरता दर लगभग 56 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 72 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 40 प्रतिशत है। यह अंतर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा, खेल और दूसरे अवसरों तक पहुंच में भी लड़कियों और लड़कों के बीच असमानता दिखाई देती है। लड़कों का मैदान में घंटों खेलना अक्सर सामान्य माना जाता है, जबकि लड़कियों के खेलते ही घर के काम, पढ़ाई, सुरूक्षा और भविष्य को लेकर सवाल उठने लगते हैं। उर्मिला के माता-पिता की सोच को केवल उनकी व्यक्तिगत सोच कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह उस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें लड़कियों के भविष्य को बचपन से ही घरेलू जिम्मेदारियों के साथ जोड़ दिया जाता है। लड़की को घर का काम सीखना चाहिए, समय पर घर लौटना चाहिए और आगे चलकर परिवार संचालना चाहिए, यह अपेक्षा इतनी सामान्य बना दी गई है कि उसके अपने सपनों के लिए समय मांगना भी कई बार अतिक्रम मांग जैसा लगने लगता है। हाल ही में ग्लासगो में हुए 2026 राष्ट्रमंडल खेलों ने यह दिखाया है कि जब महिलाओं को खेल के अवसर और प्रशिक्षण मिलते हैं तो उनकी उपलब्धियां कितनी दूर तक जा सकती हैं। भारत ने इन खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें आठ स्वर्ण अकेले महिला खिलाड़ियों ने ही जीता है। इन उपलब्धियों को केवल पदकों की संख्या के रूप में देखने के बजाय यह समझना जरूरी है कि खेल में महिलाओं की भागीदारी के लिए अवसरों का महत्व कितना बड़ा है। ग्लासगो में अस्मिता डे का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उनकी सफलता यह बताती है कि किसी खेल में अवसर और प्रशिक्षण मिलने पर महिलाएं उन क्षेत्रों में भी इतिहास रच सकती हैं, जहां भारत की उपस्थिति पहले सीमित रही है। इन महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों का मतलब यह नहीं है कि हर गांव की लड़की को ओलंपीक या राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतना ही चाहिए। असली सवाल इससे पहले का है कि क्या उसे अपनी पसंद का खेल खेलने का अवसर मिला? क्या उसके पास अभ्यास के लिए मैदान है? क्या उसे प्रशिक्षण मिलता है? क्या उसके परिवार ने उसे खेलने के लिए समय दिया?

आस्था का सम्मान, लेकिन गलत बातों पर सवाल जरूरी

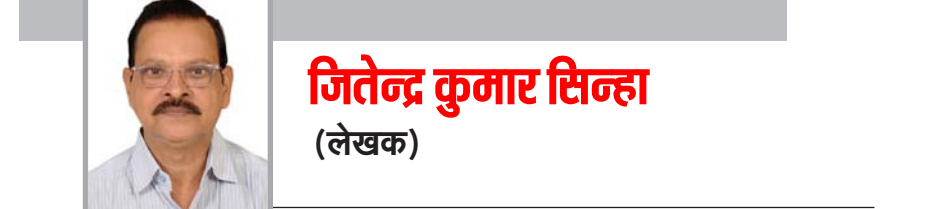
धार्मिक ग्रंथों ने हजारों वर्षों से समाज को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य, करुणा, संयम, सत्य और परोपकार का संदेश दिया है। यही कारण है कि करोड़ों लोग धार्मिक पुस्तकों को श्रद्धा के साथ पढ़ते और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी भी पुस्तक में लिखी प्रत्येक बात को बिना प्रश्न किए, बिना संदर्भ समझे और बिना तर्क की कसौटी पर परखे स्वीकार कर लिया जाए। आज सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि क्या धार्मिक पुस्तकों में लिखी हर बात को अक्षरशः सत्य मानना चाहिए? यदि किसी कथन में ऐतिहासिक परिस्थिति की छाप है, यदि वह किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है, यदि उसका अर्थ आज के संदर्भ में अलग हो गया है या यदि किसी कथन की व्याख्या मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, तो उस पर सवाल उठाना क्या धर्म-विरोध है? निश्चित रूप से नहीं। सवाल करना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और स्वस्थ समाज की पहचान भी। धर्म और आलोचनात्मक चिंतन को एक-दूसरे का विरोधी मानना एक बड़ी भूल है। आस्था व्यक्ति का निजी विश्वास हो सकती है, लेकिन जब किसी धार्मिक विचार की व्याख्या सार्वजनिक जीवन, कानून, शिक्षा, सामाजिक संबंधों या नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने लगे, तब उस विचार पर सार्वजनिक विमर्श स्वाभाविक और आवश्यक हो जाता है।



धर्म मनुष्य के जीवन में केवल पूजा-पद्धति या कर्मकांड का विषय नहीं है। वह उसकी आस्था, संस्कृति, नैतिकता, परंपरा और जीवन-दृष्टि से जुड़ा हुआ विषय है। धार्मिक ग्रंथों ने हजारों वर्षों से समाज को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य, करुणा, संयम, सत्य और परोपकार का संदेश दिया है। यही कारण है कि करोड़ों लोग धार्मिक पुस्तकों को श्रद्धा के साथ पढ़ते और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी भी पुस्तक में लिखी प्रत्येक बात को बिना प्रश्न किए, बिना संदर्भ समझे और बिना तर्क की कसौटी पर परखे स्वीकार कर लिया जाए। आज सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि क्या धार्मिक पुस्तकों में लिखी हर बात को अक्षरशः सत्य मानना चाहिए? यदि किसी कथन में ऐतिहासिक परिस्थिति की छाप है, यदि वह किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है, यदि उसका अर्थ आज के संदर्भ में अलग हो गया है या यदि

डीआईपी पर मोबाइल ग्राहकों का रहेगा पूरा डाटा - नए सिम के नियम होंगे और सख्त

नए सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में अब डिजिटल स्तर पर ग्राहक के मोबाइल कनेक्शनों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाला ग्राहक संबंधी डाटा डीआईपी पर एकत्र किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और विभिन्न सर्विस एरिया में कुल कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन किसी एक व्यक्ति के नाम पर न चले और सीमा पूरी होने के बाद उसके नाम पर नया सिम जारी न किया जाए। नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम ग्राहकों की फोटो से जुड़ा है। 23 अगस्त से डीआईपी पर उन ग्राहकों की तस्वीरें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों को ऐसी तस्वीरों को प्रतिदिन डाउनलोड करना होगा। नया मोबाइल कनेक्शन जारी करते समय कंपनी को इन तस्वीरों और उपलब्ध डाटा की जांच करनी होगी। यदि जांच में पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति पहले ही निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन ले चुका है, तो उसके नाम पर नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकेगा।



देश में मोबाइल कनेक्शन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ फर्जी सिम, एक व्यक्ति के नाम पर बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन और उन्हे संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। नए सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में अब डिजिटल स्तर पर ग्राहक के मोबाइल कनेक्शनों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाला ग्राहक संबंधी डाटा डीआईपी पर एकत्र किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और विभिन्न सर्विस एरिया में कुल कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन किसी एक व्यक्ति के नाम पर न चले और सीमा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भारत की चुनावी व्यवस्था और मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था की सार्वजनिक सराहना करना केवल दो देशों की चुनावी प्रणालियों की तुलना पर नहीं है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता भी है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से व्यापार, टेरिफ और कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे माहौल में ट्रम्प का भारत की वोटर आईडी व्यवस्था का उदाहरण देकर अमेरिका में भी चुनावी पहचान को अधिक सख्त बनाने की वकालत करना अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया मंच पर भारत की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख



सामाजिक संरचना, शासन व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान, परिवार व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियाँ अलग थीं। इसलिए किसी प्राचीन कथन का अर्थ समझने के लिए उसके मूल संदर्भ, भाषा, प्रतीकों और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। आधुनिक समय में उसी कथन की शाब्दिक व्याख्या करने से कई बार ऐसी धारणाएँ पैदा हो सकती हैं जो मूल संदर्भ से बिल्कुल अलग हों। इसीलिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि ज्ञान, इतिहास, भाषा और दर्शन की दृष्टि से भी होना चाहिए। श्रद्धा मनुष्य को प्रेरणा देती है, जबकि विवेक उसे सही अर्थ समझने में सहायता करता है। दोनों का संतुलन समाज को अधिक परिपक्व बनाता है। सबसे संवेदनशील विषय तब सामने आता है जब किसी धार्मिक कथन की व्याख्या के आधार पर स्त्री-पुरुष असमानता, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार या किसी वर्ग के प्रति घृणा को उचित ठहराने का प्रयास



कनेक्शनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रियल टाइम जांच प्रक्रिया पूरी तरह लागू होने तक निर्धारित सीमा से ज्यादा सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की निलंबित करना होगा। निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक ग्राहक के नाम पर सीमा से अधिक कनेक्शनों को बंद नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब यह है कि मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नियंत्रण केवल नया नंबर जारी करते समय ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद कनेक्शनों के मामले में भी लागू होगा। व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। शुरूआती चरण में मोबाइल कंपनियों को ग्राहक द्वारा सिम लेने के अगले दिन सत्यापन की सुविधा दी जा सकती है। यानि ग्राहक द्वारा नया सिम लेने के बाद उसके डाटा का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए रियल टाइम जांच लागू की जाएँगी। तब नया मोबाइल कनेक्शन बुक करने और उसे

कनेक्शन के समय ही यह जांच की जाएगी। रियल टाइम जांच प्रक्रिया पूरी तरह लागू होने तक निर्धारित सीमा से ज्यादा सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की निलंबित करना होगा। निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक ग्राहक के नाम पर सीमा से अधिक कनेक्शनों को बंद नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब यह है कि मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नियंत्रण केवल नया नंबर जारी करते समय ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद कनेक्शनों के मामले में भी लागू होगा। व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। शुरूआती चरण में मोबाइल कंपनियों को ग्राहक द्वारा सिम लेने के अगले दिन सत्यापन की सुविधा दी जा सकती है। यानि ग्राहक द्वारा नया सिम लेने के बाद उसके डाटा का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए रियल टाइम जांच लागू की जाएँगी। तब नया मोबाइल कनेक्शन बुक करने और उसे

कनेक्शनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रियल टाइम जांच प्रक्रिया पूरी तरह लागू होने तक निर्धारित सीमा से ज्यादा सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की निलंबित करना होगा। निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक ग्राहक के नाम पर सीमा से अधिक कनेक्शनों को बंद नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब यह है कि मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नियंत्रण केवल नया नंबर जारी करते समय ही नहीं, बल्कि पहले से मौजूद कनेक्शनों के मामले में भी लागू होगा। व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। शुरूआती चरण में मोबाइल कंपनियों को ग्राहक द्वारा सिम लेने के अगले दिन सत्यापन की सुविधा दी जा सकती है। यानि ग्राहक द्वारा नया सिम लेने के बाद उसके डाटा का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए रियल टाइम जांच लागू की जाएँगी। तब नया मोबाइल कनेक्शन बुक करने और उसे

